योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियाँ
(TARGETS AND ACHIEVEMENTS OF PLANS)

यहाँ हम आयोजन का विश्लेषण पहली नौ पंचवर्षीय योजनाओं तक ही सीमित रखेंगे। दसवीं तथा ग्यारहवीं योजनाओं पंचवर्षीय योजना की व्याख्या अलग से अध्याय 52 एवं 53 में की गई है।

1. राष्ट्रीय आय (National Income)– पहली पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का लक्ष्य क्रमशः 2.1 प्रतिशत तथा 0.9 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गया था। इसके विपरीत उपलब्धि क्रमशः 4.4 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा 1.8 प्रतिशत प्रति वर्ष थी (1999-2000 की कीमतों पर)। दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य 4.5 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गया जबकि उपलब्ध 4.0 प्रतिशत प्रति वर्ष रही। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का लक्ष्य 3.3 प्रतिशत प्रति वर्ष था जबकि उपलब्धि 2.0 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। तीसरी योजना बुरी तरह असफल रही। इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य 6.0 प्रतिशत प्रति वर्ष था जबकि उपलब्ध मात्र 2.6 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। क्योंकि यह वृद्धि लगभग जनसंख्या वृद्धि की दर के बराबर थी इसलिए प्रति व्यक्ति आय में केवल 0.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई हालांकि लक्ष्य 3.2 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि का था। चौथी योजना में राष्ट्रीय आय में मात्र 3.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई जबकि लक्ष्य 5.7 प्रतिशत प्रति वर्ष था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निष्पत्ति (performance) अपेक्षाकृत संतोषजनक थी क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादन में 4.9 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि हुई जबकि लक्ष्य 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष था (जिसे बाद में 4.4 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया था)। 1979-80 में निवल राष्ट्रीय उत्पाद में 6.0 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसे ध्यान में रखकर जब हम छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर गौर करते हैं तो वह प्रभावशाली नहीं लगती। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में 5.4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई थी। यह प्रगति अपने आप में उत्साहवर्धक लगती है। लेकिन अगले दो वर्षों में अर्थात् 1990-91 और 1991-92 में आर्थिक संवृद्धि की इस तेजी को बनाए रख पाना संभव नहीं हुआ। 1990-91 में राष्ट्रीय आय में 5.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1991-92 में राष्ट्रीय आय में केवल 0.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में 6.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई जबकि लक्ष्य 5.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय 5.3 प्रतिशत वार्षिक बढ़ी थी। लेकिन दसवीं पंचवर्षीय योजना का निष्पादन उत्साहवर्द्धक रहा और इस योजना में राष्ट्रीय आय में 7.8 प्रतिशत वार्षिक तथा प्रति व्यक्ति आय में 6.1 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई। यह पूरी योजना-अवधि में किसी योजना का सबसे अच्छा निष्पादन रहा है। परन्तु **यदि हम आयोजन की पूरी अवधि 1950-51 से 2008-09 पर विचार करें तो इसमें राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 4.3 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा 2.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दिखाई देती है जिसे एक सामान्य (modest) निष्पादन ही कहा जाएगा।**

2. बड़ा औद्योगिक क्षेत्र (Large-scale manufacturing sector)– जहां तक औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का प्रश्न है, पहली तीनों योजनाओं में यह काफी उत्साहवर्द्धक थी। वस्तुतः औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर पहली योजना में 5.7 प्रतिशत प्रति वर्ष से बढ़कर दूसरी योजना में 7.2 प्रतिशत तथा तीसरी योजना में 9.0 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई। परन्तु इसके बाद औद्योगिक मन्दी का काल शुरू हो गया और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर गिर गई। 1966 से 1976 के बीच के ग्यारह वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर गिरकर 4.1 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई। यदि 1976 को छोड़ दिया जाए (जिसमें वृद्धि 10.6 प्रतिशत थी) तो यह दर और कम होकर मात्र 3.7 प्रतिशत रह जाती है (औद्योगिक उत्पादन के पुराने सूचकांक अनुसार जब आधार 1970-71 = 100 था)।[9] इसके अलावा, शेट्टी के अनुसार निवल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा जो (1960-61 की कीमतों पर) लगातार बढ़ते-बढ़ते 1966-67 में 23.4 प्रतिशत तक पहुंच गया था उसके बाद बढ़ नहीं पाया और 1975-76 में भी 22.8 प्रतिशत था। पंजीकृत औद्योगिक क्षेत्र (registered manufacturing sector) का हिस्सा जो 1950-51 में 6.3 प्रतिशत से बढ़ते-बढ़ते 1965-66 में 10.4 प्रतिशत तक पहुंच गया था, फिर आगे नहीं बढ़ पाया और 1975-76 में भी 10.4 प्रतिशत ही था जबकि तृतीयक क्षेत्र (tertiary sector) का हिस्सा लगातर बढ़ता गया। अतः **अर्थव्यवस्था के सामने 1965-66 से ढांचागत प्रतिगमन (structural retrogression) की स्थिति उत्पन्न हो गई।** 1975-76 के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद के चार वर्षों

9. S.L. Shetty, "Structural Retrogression in the Indian Economy since the Mid-Sixties", Special Supplement of *Economic and*

Scanned with CamScanner

की अवधि (1976-77 से 1980-81 तक) में केवल 3.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई (पुराने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 1970-71=100 के आधार पर)। लेकिन **1980-81 से 1990-91 के बीच एक दशक की अवधि में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में फिर से तेजी आई और औद्योगिक उत्पादन में 7.6 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई।** 1990-91 में औद्योगिक उत्पादन में 9.0 प्रतिशत की उत्साहजनक वृद्धि हुई परन्तु 1991-92 में औद्योगिक उत्पादन में नाममात्र 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अगले वर्ष में लगभग गतिहीनता की स्थिति थी। 1993-94 से औद्योगिक पुनुरुथान शुरू हुआ और 1993-94 से 1996-97 की चार वर्षीय अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 8.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई। परन्तु नौवीं योजना (1997-98 से 2001-02) में औद्योगिक संवृद्धि को झटका लगा तथा औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दर कम होकर मात्र 5.5 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई। दसवीं योजना में स्थिति में सुधार हुआ और औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दर बढ़कर 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई। यद्यपि यह लक्षित 10.0 प्रतिशत प्रति वर्ष की संवृद्धि दर से कम थी तथापि यह पूरी योजना-अवधि में सर्वाधिक थी (तीसरी योजना को छोड़कर)। 2007-08 में औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दर 8.5 प्रतिशत थी जो 2008-09 में आर्थिक शिथिलता के कारण (जो विश्वव्यापी मंदी का परिणाम थी) कम होकर मात्र 2.6 प्रतिशत रह गई। परन्तु 2009-10 में औद्योगिक उत्पादन में 9.3 प्रतिशत की उत्साहजनक वृद्धि हुई।

3. **कृषि क्षेत्र** (Agricultural sector)– जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सम्बन्ध है, पहली योजना मे निष्पत्ति सन्तोषजनक थी। खाद्यान्नों का उत्पादन जो 1950 में 5.40 करोड़ टन था, 1955-56 में 6.48 करोड़ टन हो गया जबकि लक्ष्य 6.16 करोड़ टन का था। तिलहनों के लिए उपलब्धि भी लक्ष्य से अधिक थी जबकि रुई में उपलब्धि लक्ष्य से जरा कम थी। परन्तु पटसन और गन्ने के क्षेत्र में उपलब्धि लक्ष्य से काफी कम थी। दूसरी योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 7 करोड़ 50 लाख टन रखा गया था जबकि उपलब्धि 7 करोड़ 60 लाख टन थी। तिलहनों और गन्ने का उत्पादन लक्ष्य से अधिक था जबकि पटसन का लक्ष्य से कम। तीसरी योजना में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 10 करोड़ टन रखा गया परन्तु इस योजना का अन्तिम वर्ष, 1965-66, सूखे का वर्ष था जिससे उपलब्धि मात्र 7 करोड़ 20 लाख टन रह गई। इससे पहले वाले वर्ष (1964-65) में उत्पादन 8 करोड़ 90 लाख टन था। **तीसरी योजना की कृषि क्षेत्र में निष्पत्ति काफी निराशाजनक कही जा सकती है क्योंकि अधिकतर फसलों का उत्पादन लक्ष्य से कम था।** चौथी योजना में खाद्यान्नों के लक्ष्य 12 करोड़ 90 लाख टन की तुलना में 1973-74 में उत्पादन मात्र 10 करोड़ 47 लाख टन था। अधिकतर वाणिज्यिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, रुई, तिलहन इत्यादि का उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में कम था। पूरे कृषि उत्पादन को एक साथ देखें तो चौथी योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य 5 प्रतिशत प्रति वर्ष था जबकि उपलब्धि मात्र 2.8 प्रतिशत थी। पाँचवीं योजना में 1978-79 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 14 करोड़ टन रखा गया जबकि उपलब्धि 13 करोड़ 19 लाख टन रही। गन्ना उत्पादन का लक्ष्य 17 करोड़ टन रखा गया जबकि उपलब्धि 15 करोड़ 17 लाख टन रही। रुई का उत्पादन 79.6 लाख गाँठ था जबकि लक्ष्य 80 लाख गाँठों का था। छठी पंचवर्षीय योजना में अच्छी फसल होने के कारण 1983-84 में खाद्यान्नों का उत्पादन 15 करोड़ 24 लाख टन हो गया। परन्तु 1984-85 में यह गिरकर 14 करोड़ 62 लाख टन हो गया (लक्ष्य 14 करोड़ 90 लाख टन से 15 करोड़ 40 लाख टन के बीच था)। रुई, पटसन तथा गन्ने का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा। तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि की निष्पत्ति एक बार फिर संतोषजनक नहीं थी। इस योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्य 17 करोड़ 80 लाख टन था जबकि योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 1989-90 मे केवल 17 करोड़ 10 लाख टन उत्पादन हुआ। सातवीं योजना के अंतर्गत तिलहन और जूट के भी उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके लेकिन योजना के अन्तिम वर्ष में रुई और गन्ने का उत्पादन सातवीं योजना के लक्ष्य से अधिक था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 21 करोड़ टन रखा गया परन्तु योजना के अन्तिम वर्ष 1996-97 में खाद्यान्नों का वास्तविक उत्पादन 19 करोड़ 90 लाख टन ही हो पाया। तिलहन, गन्ने, रूई और पटसन के उत्पादन में थोड़ी वृद्धि ही हो पाई। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 2001-02 में खाद्यान्नों का उत्पादन 21 करोड़ 20 लाख टन था। तिलहन, रूई तथा पटसन के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। गन्ने का उत्पादन 1996-97 के उत्पादन की तुलना में थोड़ा सा ही अधिक था। नई कृषि नीति 2000 में कृषि नीति के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की संवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप दसवीं योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष का संवृद्धि लक्ष्य रखा गया। योजना के अन्तिम वर्ष 2006-07 में खाद्यान्नों की अनुमानित मांग 23 करोड़ 60 लाख टन थी जबकि आपूर्ति केवल 21 करोड़ 73 लाख टन रही। 2007-08 में खाद्यान्नों का उत्पादन 23 करोड़ 8 लाख टन तथा 2008-09 में 23 करोड़ 39 लाख टन तक पहुँच गया। परन्तु कृषि क्षेत्र में संवृद्धि दर जो 2007-08 में 4.7 प्रतिशत थी, 2008-09 में गिर कर 1.6 प्रतिशत तथा 2009-10 में मात्र 0.2 प्रतिशत रह गई।

Scanned with CamScanner

4. भुगतान संतुलन (Balance of payments)– आयोजन के पहले चार दशकों में भुगतान संतुलन के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं की निष्पत्ति निराशाजनक रही है। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1989-90) तक लगातार व्यापार शेष (Balance of trade) भारत के प्रतिकूल था (केवल दो वर्षों 1972-73 तथा 1976-77 को छोड़कर जब व्यापार शेष में क्रमशः 103 करोड़ तथा 69 करोड़ रुपये का अधिशेष था)। योजनावधि के अधिकांश वर्षों में अदृश्य मदों (invisible items) से आय धनात्मक थी परन्तु यह व्यापार शेष के भारी घाटों को पूरा करने में बिल्कुल असमर्थ थी। परिणाम यह हुआ कि भुगतान संतुलन भी भारत के प्रतिकूल रहा और इसके घाटों को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता का सहारा लेना पड़ा। समस्या की गम्भीरता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भुगतान संतुलन में घाटा (चालू खाते में) जो पहली योजना में केवल 42.3 करोड़ रुपये था, दूसरी योजना में बढ़कर 1,647 करोड़ रुपये, तीसरी योजना में 1,972 करोड़ रुपये तथा तीन वार्षिक योजनाओं में 2,015 करोड़ रुपये हो गया। चौथी योजना में 1973-74 के लिए निर्यात से आय का लक्ष्य 1,900 करोड़ रुपये रखा जबकि 1968-69 में निर्यात से आय 1,360 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार निर्यात आय में वृद्धि का लक्ष्य 7 प्रतिशत प्रति वर्ष था। इस योजना के अन्तिम दो वर्षों में निर्यात आय में तेज वृद्धि हुई जिससे पूरे योजना काल के लिए निर्यात आय में वृद्धि की दर 13.6 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गई। परन्तु इस अच्छी निष्पत्ति से भी समस्या की गम्भीरता कम नहीं हुई क्योंकि तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों में वृद्धि कर दी जिससे तेल पर आयात व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चौथी योजना में व्यापार शेष में 1,564 करोड़ रुपये तथा भुगतान संतुलन में 2,221 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चालू खाते में 1,403.7 करोड़ रुपये का अधिशेष था परन्तु पूँजी खाते में काफी घाटा होने के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति असन्तोषजनक थी। छठी पंचवर्षीय योजना में आयोजकों को व्यापार शेष में 17,773 करोड़ रुपये का घाटा होने की आशा थी जबकि अदृश्य मदों से 8,710 करोड़ रुपये का लाभ अनुमानित था। इस प्रकार भुगतान संतुलन में अनुमानित घाटा 9,063 करोड़ रुपये था। इस अनुमान के विपरीत छठी योजना में (चालू खाते में) वास्तविक घाटा 11,885 करोड़ रुपये हुआ जो अनुमानित घाटे से 25.6 प्रतिशत अधिक था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भुगतान संतुलन की स्थिति पर अभूतपूर्व दबाव था। इस योजना की अवधि में व्यापार शेष में 54,205 करोड़ रुपये का घाटा था जबकि अदृश्य मदों से निवल आय केवल 13,158 करोड़ रुपये हुई। फलतः भुगतान संतुलन के चालू खाते में 41,012 करोड़ रुपये का घाटा रहा। 1990-91 में पैट्रोलियम की कीमतों में भारी वृद्धि और खाड़ी देशों में युद्ध के कारण अदृश्य मदों के अंतर्गत निवल आय में भारी कमी से भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा 17,369 करोड़ रुपये का रहा। इस गंभीर स्थिति का सामना आयात में भारी कटौती द्वारा किया गया और इस तरह 1991-92 में चालू खाते में घाटा 2,237 करोड़ रुपये के लगभग रहा। आठवीं पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि में चालू खाते पर कुल 55,000 करोड़ रुपए का घाटा अनुमानित था परन्तु वास्तविक घाटा 62,900 करोड़ रुपए रहा। परन्तु कुल मिलाकर स्थिति संतोषजनक थी क्योंकि पूंजी खाते पर काफी अन्तर्प्रवाह प्राप्त हुए।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में विदेशी क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। पूरी योजना के दौरान चालू खाते पर 1,59,800 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान था जबकि वास्तविक घाटा केवल 53,175 करोड़ रुपए रहा। योजना के अन्तिम वर्ष 2001-02 में चालू खाते पर 16,426 करोड़ रुपए का अधिशेष था। अगले दो वर्षों में भी चालू खाते पर अधिशेष प्राप्त हुआ (कुल अधिशेष 94,643 करोड़ प्राप्त था)। स्वतन्त्रता के बाद यह पहला मौका था जब लगातार तीन वर्ष तक चालू खाते पर अधिशेष प्राप्त हुआ था। दसवीं योजना के शेष तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07) में फिर चालू खाते पर घाटा हुआ और यह घाटा 1,00,294 करोड़ रुपए था। इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना की पूरी अवधि में केवल 5,671 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस बात को देखते हुए कि इस योजना में पूंजी खाते पर काफी अधिशेष प्राप्त हुआ था, भुगतान संतुलन की स्थिति संतोषजनक थी। 2007-08 में चालू खाते पर घाटा 68,914 करोड़ रुपए था जो 2008-09 में बढ़कर कर 1,32,271 करोड़ रुपए तक जा पहुँचा (यह योजना-अवधि में किसी एक वर्ष में होने वाला सर्वाधिक घाटा था)। पूंजी खाते पर अधिशेष में भी गिरावट हुई। 2007-08 में पूंजी खाते पर अधिशेष 4,38,603 करोड़ रुपए था जो 2008-09 में कम होकर मात्र 35,516 करोड़ रुपए रह गया। इस प्रकार वर्ष 2008-09 में भुगतान सन्तुलन की स्थिति काफी खराब रही। इसका मुख्य कारण इस वर्ष होने वाली विश्वव्यापी मंदी थी।

5. बचत और निवेश की दरें (Rates of saving and investment)– सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू निवेश के आंकड़ों से स्पष्ट है कि आयोजन काल के पहले दो दशकों में सकल घरेलू बचत और सकल घरेलू निवेश दरों में नियमित रूप से वृद्धि हुई थी। 1950-51 में जहां निवेश दर सकल घरेलू उत्पाद की 8.4 प्रतिशत थी, वहां बचत दर 8.6 प्रतिशत थी (आधार वर्ष 1999-2000)। घरेलू पूंजी निर्माण की दर अर्थात निवेश दर 1960-61 में 14.0 प्रतिशत और 1970-71 में 15.1 प्रतिशत हो गई

Scanned with CamScanner

थी। इसकी तुलना में बचत दर 1960-61 में 11.2 प्रतिशत और 1970-71 में 14.2 प्रतिशत थी। स्पष्ट है कि निवेश और बचत दरों में अन्तर विदेशी पूँजी से पूरा किया गया। चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश और बचत दरों में काफी कमी हुई। उदाहरण के लिए, चौथी योजना के अंतिम वर्ष में घरेलू पूंजी निर्माण की दर 17.0 प्रतिशत थी जबकि घरेलू बचत दर 16.4 प्रतिशत थी। इस तरह दोनों में केवल 0.6 प्रतिशत का अंतर था। पांचवीं योजना की निष्पत्ति और भी अच्छी थी क्योंकि इस योजना के तीन वर्षों में तो बचत दर घरेलू पूँजी निर्माण की दर से अधिक थी। 1980-81 में घरेलू पूंजी निर्माण की दर जहां 19.9 प्रतिशत थी वहाँ घरेलू बचत दर 18.5 प्रतिशत थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बचत और निवेश दरों में कमी हुई। 1984-85 में जहां घरेलू बचत दर 18.2 प्रतिशत थी वहां घरेलू निवेश दर 19.6 प्रतिशत थी। इस तरह दोनों में 1.4 प्रतिशत का अंतर था जिसे विदेशी पूँजी के आयात से पूरा किया गया। सातवीं योजना में बचत और निवेश दर दोनों में वृद्धि हुई। इस योजना के अन्तिम वर्ष 1989-90 में बचत दर 21.8 प्रतिशत तथा निवेश दर 24.3 प्रतिशत थी। आर्थिक सुधारों की अवधि में इन दोनों दरों में तेज़ वृद्धि हुई है। आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष 1996-97 में बचत दर 22.7 प्रतिशत तथा निवेश दर 24.0 प्रतिशत थी। नौवीं योजना के अन्तिम वर्ष 2001-02 में बचत दर 23.5 प्रतिशत तथा निवेश दर 22.8 प्रतिशत थी। दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष 2006-07 में बचत दर 37.5 प्रतिशत तथा निवेश दर 36.9 प्रतिशत के उच्च स्तर तक पहुँच गई। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने अब 2004-05 को आधार वर्ष मान कर वर्ष 2004-05 से बचत और निवेश दर की नई श्रृंखला प्रस्तुत की है। इस नई श्रृंखला के अनुसार 2004-05 में बचत दर 34.4 प्रतिशत तथा निवेश दर 35.5 प्रतिशत थी। 2008-09 में बचत दर 32.5 प्रतिशत तथा निवेश दर 34.9 प्रतिशत थी (आधार वर्ष 2004-05)।

Scanned with CamScanner